

स्मार्ट पीडीएस योजना

प्रासंगिकता: जीएस-3: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, लामबंदी से संबंधित मुद्दे।

की-वर्ड्स: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, महिला और बाल विकास, और यूआईडीएआई, वन नेशन वन राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकान, ई- श्रम पोर्टल, आयुष्मान भारत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय।



प्रसंग:

- स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (SMART-PDS) योजना भारत सरकार द्वारा देश के सबसे बड़े लाभार्थी-केंद्रित कार्यक्रम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को डिजिटलाइज़ और आधुनिक बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है।

मुख्य विचार:

- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) की स्मार्ट पीडीएस पहल का उद्देश्य विश्वसनीय और गतिशील डेटा की कमी को दूर करने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने को लागू करना है।
- योजना लाभार्थियों के उपभोग और गतिशीलता पैटर्न की पहचान करने के लिए खाद्यान्न के वितरण से उत्पन्न डेटा का लाभ उठाती है।
- इस डेटा का उपयोग समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है।
- डेटा एनालिटिक्स और अन्य आईसीटी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग भी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पीडीएस संचालन के मानकीकरण की अनुमति देगा और इसे एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, रेल और सड़क की परिवहन आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास और यूआईडीएआई के साथ एकीकृत करेगा।
- एआई के उपयोग के साथ अभिसरण और एकीकरण वास्तव में सभी कार्यक्रमों में जवाबदेही लाने में लोगों के साथ-साथ सरकारों के लिए गेम चेंजर हो सकता है।

महत्व:

- **लक्षित वितरण:** स्मार्ट-पीडीएस योजना के प्राथमिक लाभों में से एक यह है कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं की लक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करता है। **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)** जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के आंकड़ों का लाभ उठाकर, यह योजना प्रत्येक राज्य में सबसे कमजोर परिवारों की पहचान करती है और तदनुसार संसाधनों का आवंटन करती है।
- **चोरी को समाप्त करना :** **SMART-PDS** योजना लीकेज को खत्म करने, खाद्यान्न की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चोरी को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटाइज्ड राशन कार्ड और **इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ePoS) उपकरणों जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करती है।** यह सुनिश्चित करता है कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही लाभ प्राप्त करें और खाद्यान्न के डायवर्जन या कालाबाजारी को रोका जा सके।
- **पारदर्शिता में वृद्धि:** स्मार्ट-पीडीएस योजना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संसाधनों के आवंटन और खाद्यान्न के वितरण के बारे में जानकारी एकत्रित कर वितरण प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है। इससे लाभार्थियों के लिए अपनी पात्रताओं के बारे में जानकारी हासिल करना आसान हो जाता है और अधिकारियों को किसी भी तरह की विसंगतियों या लाभों के वितरण में देरी के लिए **जवाबदेह ठहराया जा सकता है।**
- **लागत और संसाधनों की बचत:** योजना यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों को वास्तविक जरूरतों के आधार पर आवंटित किया जाए, जिससे खाद्यान्न और अन्य संसाधनों की बर्बादी कम हो। इससे **लागत बचाने में भी मदद मिलती है क्योंकि सरकार लाभार्थियों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर अपने संसाधनों का अनुकूलन कर सकती है।**
- **जवाबदेहीता में वृद्धि:** स्मार्ट-पीडीएस योजना जवाबदेहीता को बढ़ाती है क्योंकि यह लाभार्थियों को अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह योजना **वितरण प्रणाली की निगरानी और मूल्यांकन की भी अनुमति देती है**, जिससे अधिकारियों के लिए सिस्टम में किसी भी कमियों को ट्रैक करना और सुधारना आसान हो जाता है।

स्मार्ट-पीडीएस से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- **तकनीकी बाधाएँ:** स्मार्ट-पीडीएस योजना से जुड़ी प्राथमिक चुनौतियों में से एक तकनीकी बाधा है। यह योजना प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल राशन कार्ड और **इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ePoS) डिवाइस शामिल हैं।** हालांकि, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बहुत से लोग इन तकनीकों से परिचित नहीं हैं, जिससे उनके लिए अपने अधिकारों तक पहुंच बनाना मुश्किल हो जाता है।
- **जागरूकता की कमी:** स्मार्ट-पीडीएस योजना से जुड़ी एक अन्य चुनौती लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी है। हो सकता है कि कई लाभार्थियों को अपनी पात्रता या उन तक पहुंचने के तरीके के बारे में पता न हो, जिससे योजना का कम उपयोग हो सकता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां:** स्मार्ट -पीडीएस योजना को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। हालांकि, भारत में कई क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढाँचा नहीं है, जैसे कि **इंटरनेट कनेक्टिविटी**, बिजली आपूर्ति और भंडारण सुविधाएं, जिससे योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो जाता है।
- **भ्रष्टाचार और किराए की मांग:** स्मार्ट-पीडीएस योजना में इस्तेमाल की गई उन्नत तकनीक के बावजूद, भ्रष्टाचार और किराया मांग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। कुछ अधिकारी और बिचौलिए अभी भी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने या बेईमानी करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कमजोर प्रशासन और निगरानी व्यवस्था है।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)

- भारत सरकार ने टीपीडीएस संचालन योजना के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण द्वारा लाए गए सुधारों को बनाए रखने और योजनाकारों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस) योजना शुरू की है।
- योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) का कार्यान्वयन है – यह एक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी योजना है, जो लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने लिए राशन लेने की अनुमति देती है।
- यह योजना सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है और लगातार 3.5 करोड़ से अधिक मासिक पोर्टेबल लेनदेन रिकॉर्ड कर रही है।
- अगस्त 2019 में केवल चार राज्यों में अपनी स्थापना के बाद से, ओएनओआरसी ने अब तक 100 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन पूर्ण किए हैं।

निष्कर्ष:

- स्मार्ट-पीडीएस योजना डिजिटलीकरण में एक साहसिक पहल है जिसने समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है।
- स्मार्ट पीडीएस योजना का दायरा स्पष्ट रूप से सिर्फ राशन वितरण से परे है और सभी सरकारी योजनाओं में अधिक जवाबदेहीता की स्थापना करेगा।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. स्मार्ट पीडीएस खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की पहल है।
2. वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) - एक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी योजना है जो लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने लिए राशन प्राप्त करने की अनुमति देती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- स्मार्ट पीडीएस खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) की पहल है। कथन 1 सही है।
- वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) - एक राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी योजना है जो लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने भोजन राशन तक पहुंचने की अनुमति देती है। कथन 2 सही है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के वितरण के लिए स्मार्ट-पीडीएस योजना के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द)